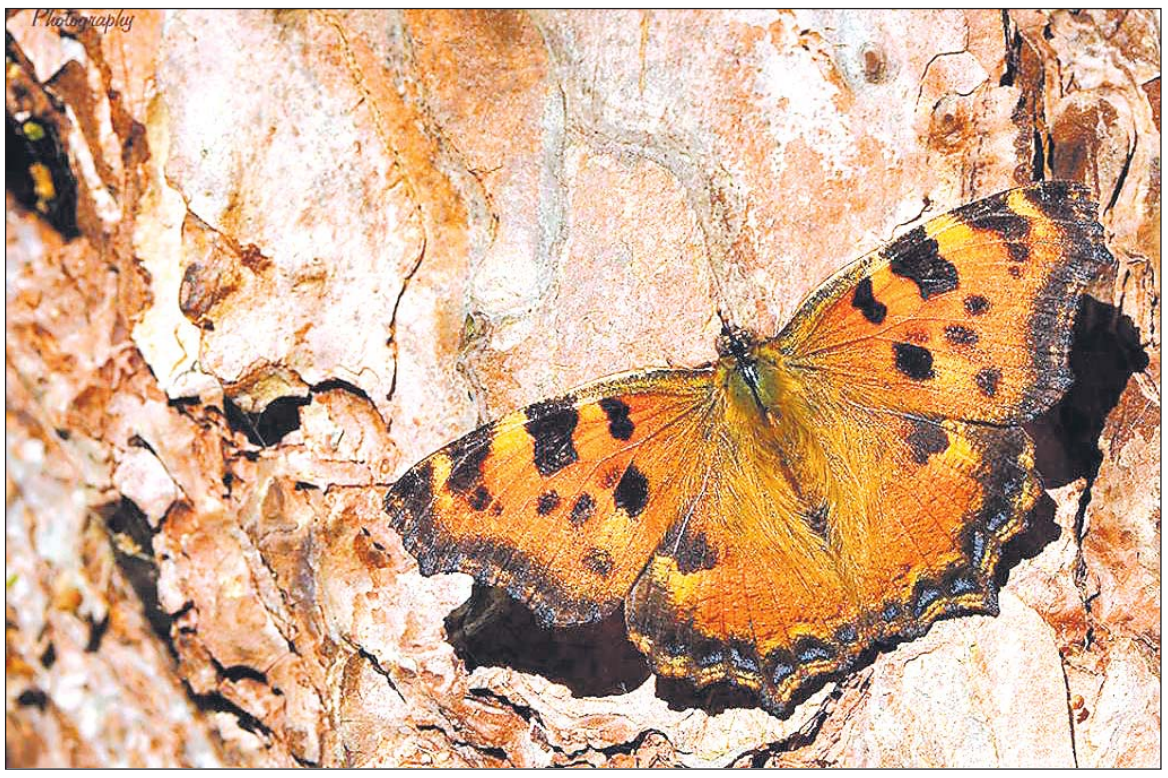


*हो सकता है कि दुनियाभर में उड़ने वाले कीट-पतंगों की संख्या में चिंताजनक कमी आ रही हो, लेकिन एक अच्छी खबर है कि, एक तितली की संख्या में फिर से वृद्धि होने लगी है। तितली की एक प्रजाति, लार्ज टॉरटिस शैल बटरफ्लाई, जो विश्वयुद्ध के बाद अज्ञात कारणों से ब्रिटेन में लुप्त हो गई थी, अब फिर से दिखने लगी है। माना जा रहा है कि, यदाकदा यूरोप के अन्य देशों से ब्रिटेन में इनका जो आगमन हुआ उसके कारण एक बार फिर ब्रिटेन में इनकी ब्रीडिंग कॉलोनीज़ बन गईं। तितली विशेषज्ञ नील ह्यूम ने कहा, कई शौकिया ब्रीडर्स तितलियों को अनाधिकृत रुप से रिलीज़ करके काम बिगाड़ते हैं। ह्यूम कई वर्षों से इस रहस्यमय जीव की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि, इतनी बार इन तितलियों की प्रमाणिक साइटिंग हुई है कि, यह नहीं कह सकते कि ये सब संरक्षित प्रजनन केन्द्रों वाली तितलियाँ हैं। इस वर्ष गर्मी में ईस्ट ससैक्स के तीन वर्ग मील क्षेत्र में इस तितली के लार्वा के तीन झुंड मिले थे और हाल ही में उस जगह नव वयस्क तितलियाँ देखी गई हैं। ह्यूम का कहना है कि, वर्ष 2007 में यूरोप के कई भागों से ब्रिटेन में जो बड़ा माइग्रेशन हुआ वो इनकी वापसी का कारण हो सकता है। हालांकि आइल ऑफ वाइट में स्थापित ब्रीडिंग कॉलोनी खत्म हो गई, लेकिन इस वर्ष फिर इस द्वीप पर यह तितली देखी गई है। इसके अलावा नॉर्थ कैंट के एल्मली नैशनल रिज़र्व में भी ये तितलियां देखी गई हैं। धरती का बढ़ता तापमान दुनियाभर में चिंता का विषय है पर इसी वजह से यह खूबसूरत तितलियाँ ब्रिटेन में बस रही हैं।*

# ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होना तय नहीं

## ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले ब्रिक्स समूह की 15वीं शिखर बैठक आज से जोहनिसबर्ग में शुरू होगी

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के शीर्ष नेता शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना के बारे में यहां विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अभी तक इस बारे में कुछ भी तय नहीं है।

ब्रिक्स में नए सदस्य जोड़ने के बारे में भारत का कहना है कि 'वह इसके पक्ष में खुली सोच रखता है' पर इस बारे में कोई भी निर्णय समूह के नियम और सदस्यों की आम सहमति से ही लिया जा सकता है।

विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रधानमंत्री की मंगलवार से शुरू हो रही दक्षिण अफ्रीका और यूनान की चार दिन की यात्रा के विषय में जानकारी देने के लिए आयोजित विशेष मीडिया ब्रीफिंग में मोदी की चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की संभावनाओं के बारे में एक सवाल पर कहा, 'मैं केवल यही कह सकता हूं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने बड़ी संख्या में विभिन्न देशों को आमंत्रित कर रखा है। इस दौरान मोदी की वहां आने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों के कार्यक्रम को तैयार किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तय हो जाने पर आप को (मीडिया को) इसकी सूचना दे दी जाएगी।'

**24-इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि, भारत ब्रिक्स में और देशों को जोड़ने की प्रक्रिया का खुला समर्थन करेगा। 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है 23 देशों ने आवेदन भी कर रखा है।**

- **अगर कुछ और देश जुड़ते हैं तो जाहिर है ब्रिक्स दुनिया का आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर संगठन बन जायेगा।**

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले ब्रिक्स समूह की 15वीं शिखर बैठक कल से जोहान्सबर्ग में शुरू हो रही है। वहां ब्रिक्स के संपर्क विस्तार कार्यक्रम के तहत 24 अगस्त को 'ब्रिक्स सम्पर्क सम्मेलन' और ब्रिक्स प्लस सम्मेलन के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है।

मोदी वहां से 25 अगस्त को यूनान की एक दिन की आधिकारक यात्रा पर एथेंस जाएंगे। विदेश सचिव ने बंगलादेश के मामलों में अमेरिका की कथित 'ताजा विशेष रुचि पर भारत के रुख' के संदर्भ में प्रधानमंत्री शेख हसीना से जोहान्सबर्ग में मुलाकात की संभावना के संबंध में पूछे जाने पर भी कहा कि कार्यक्रम तय हो जाने पर ही इस संबंध में कोई जानकारी दी जा सकती है।

ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार से संबंधित एक सवाल पर विदेश सचिव ने कहा, ''सदस्यता विस्तार के संबंध में भारत की सोच सकारात्मक और खुली है। समूह की सदस्यता के नियम और शर्तें हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पर ब्रिक्स सेरपाओं की बैठक में तकनीकी चर्चाएं हो रही है और ब्रिक्स में निर्णय 'सर्वसम्मति' से लिए जाते हैं।

एक अन्य सवाल के जवाब में क्वात्रा ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच आंतरिक व्यापार में सदस्य देशों के प्रयोग को बढ़ाने की तो बात है पर साझा मुद्रा लागू करने का विचार नहीं है। उन्होंने कहा 'साझा मुद्रा एक अलग अवधारणा है।' ऐसा समझा जाता है कि 40 से अधिक देश ब्रिक्स की सदस्यता की इच्छा प्रकट कर चुके हैं और 23 देशों ने आवेदन कर रखा है।

उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय व्यापार में लेन देन राष्ट्रीय मुद्राओं (रुपया-दिरहम) में किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। इस मॉडल की प्रगति के साथ भारत इसे दूसरे देशों के साथ भी अपनाने पर विचार कर सकता है। चीन ब्रिक्स विस्तार प्रक्रिया का समर्थन करेगा और संगठन में नए भागीदारों के शीघ्र प्रवेश का स्वागत भी करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रेस सेवा ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने ब्रिक्स से पहले कहा, चीन का हमेशा से मानना रहा है कि ब्रिक्स एक खुला और समावेशी तंत्र है, बीजिंग ब्रिक्स विस्तार प्रक्रिया का समर्थन करता है और अधिक समान विचारधारा वाले भागीदारों के ब्रिक्स बड़े परिवार में शीघ्र प्रवेश का स्वागत करता है।

## 'प्रदेश की सभी बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वोटर होना जरूरी है परंतु जिस रवैये से यह चुनाव हो रहा है उस रवैये से जाहिर हो रहा है कि, एसोसिएशन चाहती है कि, कई लोग चुनाव ना लड़ें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि, द बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2022 को फैसला दिया था। उसके बाद द बार एसोसिएशन, जयपुर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने किन्हीं अन्य बार एसोसिएशन में केवल शपथ पत्र ही दिया था और मतदान नहीं किया था। ऐसे में उन्हें इस चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए।

बी.सी.आर. के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि, ''वन बार वन वोट'' के पालन में ही चुनाव समिति शपथ पत्र मांग रही है। बी.सी.आर. की ओर से यह भी कहा गया कि, कई वकील झूठे शपथ पत्र भी दायर करते हैं। बी.सी.आर. की ओर से कहा गया कि, प्रत्येक बार एसोसिएशन का अलग-अलग संविधान है और समितियों के चुनाव की तारीख भी अलग-अलग हैं। इसलिए अदालत यह तय कर दे कि जिन वकीलों ने एक वर्ष में एक बार के लिये वोट दिया है, वो उस समिति के कार्यकाल या उस वर्ष में होने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे। इस पर खंडपीठ ने कहा कि, इस समस्या का समाधान यही है कि, सभी बार एसोसिएशन में एक ही तारीख को चुनाव हों।

दरअसल अपीलों में बार एसोसिएशन के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव में 28 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में लिए जा रहे शपथ पत्र की शर्त को चुनौती दी गई है।

# धरना-प्रदर्शन के लिए शहर को चार भागों में बांटा, दिन में चार घंटों के लिए मिलेगी अनुमति

## राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में, धरना प्रदर्शन के कारण होने वाले जाम से बचने का रोडमैप प्रस्तुत किया

- **कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम चार बजे से रात 8 बजे तक धरना-प्रदर्शन या रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चार घंटे की अवधि में ही धरना-प्रदर्शन किया जा सकेगा।**

जयपुर, 21 अगस्त। राज्य सरकार ने शहर में होने वाले धरने-प्रदर्शन और रैली के कारण वाले जाम को रोकने के लिए शहर को चार भागों में बांट दिया है और प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से हर ज़ोन में कुछ जगहें चिन्हित की हैं। सरकार ने यह फैसला भी किया है कि कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपरान्ह चार बजे से शाम 8 बजे के बीच की अवधि में धरना-प्रदर्शन और रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रैली के लिए दोपहर 12 बजे से अपरान्ह चार बजे तक ही अनुमति दी जा सकगी।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 1 सितंबर को रखी है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।

राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि धरने-प्रदर्शन और रैली के लिए जयपुर पूर्व में दो हजार तक की भीड के लिए महात्मा गांधी स्टेडियम, बस्सी, पांच हजार तक की भीड के लिए दशहरा मैदान, आदर्श नगर और सूरज मैदान आदर्श नगर का चयन किया गया है और पांच से दस हजार तक की भीड के लिए रामलीला मैदान, एमआई रोड को चयनित किया है। जयपुर पश्चिम में दो हजार तक की भीड के लिए करघनी स्कीम पार्क, पांच से दस हजार तक की भीड के लिए खेल स्टेडियम, चौमूं और खेल मैदान बगरू, दस हजार से अधिक की भीड के लिए भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान और जेसीबी प्लांट महिंन्द्रा सेज का चयन किया गया है।

जयपुर उत्तर के लिए दो हजार से अधिक लोगों की भीड के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम के सामने खाली मैदान को चिन्हित किया गया है। जयपुर दक्षिण में दो हजार तक की भीड के लिए शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल, पांच हजार से दस हजार तक की भीड के लिए वीटी रोड स्थित आवासन मंडल की खाली जमीन का चयन किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से अपने जवाब में कहा गया है कि कार्य दिवस में रैलियों के लिए दोपहर 12 बजे से अपरान्ह चार बजे तक का समय ही दिया जाएगा। इस दौरान ध्वनि प्रसारण यंत्र का सीमित उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यह अनुमति अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोर्ट और कार्यालय भवनों से 150 मीटर की परिधि में इन संस्थाओं की समयावधि के लिए मान्य नहीं रहेगी।

कार्यक्रम के दौरान यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि गत एक अगस्त को भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत निकाली गई रैली के चलते शहर का यातायात जाम होने पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।

## अब कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(कांग्रेस में) आने से कैसे रोक सकता हूँ क्योंकि पूरे राज्य में लोग देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें किसी से किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। राजनेताओं को अपने राजनैतिक भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का अधिकार है।''

भाजपा नेता विधायकों को कांग्रेस में जाने से रोकने के काम में जुट गये हैं क्योंकि पूर्व कांग्रेसी, जो इस समय भाजपा में हैं, कम से कम 12 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस उन भाजपा विधायकों को फिर से वापस लेना चाहती है, और भाजपा नेता भी उन्हें पार्टी छोड़ने से इसीलिये रोकना चाहते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येद्दियुरप्पा, जिन्हें कांग्रेस विधायकों की 2019 की बगावत का सीधा लाभ मिला था से भी घर वापसी को रोकने के लिये कहा गया है। देखना यह भी है कि पूर्व कांग्रेसी विधायक उनकी बात मानते हैं या नहीं। उधर जनता दल (एस) ने कहा है कि कांग्रेस की घर वापसी की मुहिम का उद्देश्य अपनी असफलताओं, तबादलों में हुये भ्रष्टाचार तथा कमीशन खोरी से जनता का ध्यान हटाना है। ये आरोप लगाते हुये, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, ''क्या हम उन्हें रोक सकते हैं, जो जाना चाहते हैं? पार्टी के प्रति निष्ठा नाम की चीज अब बची ही नहीं है। मैं इस बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्षी विधायकों के सम्पर्क में है।

## '2024 में एन.डी.ए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पी. आम तौर से उस दल या गठबंधन को अपना समर्थन देती हैं, जो केन्द्र में सरकार बनाता है, वहीं भारत राष्ट्र समिति (बी.आर.एस.) अपने भाजपा-विरोधी रूख के लिये जानी जाती है। अगर बी.आर.एस. के वोट शेयर को अनुमानतः 1.15 प्रतिशत मान लिया जाये, तथा उसे इंडिया ब्लॉक ब्लॉक के शेयर में शामिल कर दिया जाये, तो विपक्षी खेमे का कुल वोट शेयर बढ़कर 41.35 प्रतिशत हो जाता है- अर्थात एन.डी.ए. के वोट शेयर से मात्र 1.25 प्रतिशत कम।

अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं ऐसे में कोई भी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि संवेदनशील या अचानक होने वाले तत्वों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि विदित ही है, ये चीजें देश के राजनैतिक माहौल को बदलने की क्षमता रखते हैं- ठीक वैसे ही, जैसे पुलवामा तथा बालाकोट की घटनाओं ने 2019 में प्रवाह को भाजपा के पक्ष में मोड़ दिया था। इस समय केवल इतना ही कहा जा सकता है- विपक्षी दलों के पक्ष में बेहतर अवसर उभर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के लिए, खासतौर से हिन्दी भाषी राज्यों में, वोट शेयर को सीटों का रूप देना एक बड़ी चुनौती होगी। जहाँ भाजपा के वोट मुख्यतः हिन्दी भाषी राज्यों में घनीभूत हैं, वहीं इंडिया के वोट पूरे भारत में फैले हुये हैं। आगामी महीनों में, विपक्षी गठबंधन को ए अखिल भारतीय सक्रियता बनाने तथा उसे बनाये रखने की जरूरत होगी, ताकि 2024 में भाजपा को एक भरोसेमंद टक्कर दी जा सके।

# भाजपा सांसद सनी देओल के बंगले की नीलामी ऐन वक्त पर रद्द की गई

## बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन डिफॉल्ट मामले में तकनीकी कारणों का हवाला देकर बंगले की नीलामी का नोटिस वापस लिया

- **बैंक ने सनी देओल के 56 करोड़ रु. का बंगला नीलाम करने का नोटिस जारी किया था तथा 25 अगस्त नीलामी होना तय थी।**

नई दिल्ली, 21 अगस्त। फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी रोक दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपये वसूलने के लिए सनी देओल के बंगले को नीलाम करने का नोटिस जारी किया था लेकिन अब बैंक ने उस ई-ऑक्शन की नोटिस को वापस ले लिया है।

बैंक ने इसकी पीछे तकनीकी कारण बताया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के इस यू-टर्न पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चुटकी ली है और तंज कसा है कि 24 घंटे के अंदर यह तकनीकी कारण कहां से आ गया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, कल दोपहर में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू में स्थित आवास को ई-नीलामी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने बैंक का 56 करोड़ रुपये नहीं चुकाया है। आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आश्चर्य है कि ऐसे कौन से तकनीकी कारण हैं, जिसके कारण यह फैसला बदला गया।''

उन्होंने सवाल किया, आखिर इन तकनीकी कारणों का हवाला देने के लिए किसने प्रेरित किया? बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सनी देओल की संपत्ति को नीलामी के लिए रखा था। यह नीलामी 25 अगस्त को ऑनलाइन माध्यम से की जानी थी।

# सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को 28 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने एक दुष्कर्म पीड़िता को करीब 28 सप्ताह के अपने भ्रूण का गर्भपात कराने की सोमवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आदेश पारित करते कहा कि विवाह के बाद गर्भधारण खुशी का अवसर होता है, लेकिन यौन उत्पीड़न के बाद यह महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीठ ने 25 साल की एक महिला की याचिका से संबंधित मैडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद याचिकाकर्ता से गर्भावस्था समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसे मंगलवार को अस्पताल आने को कहा।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल को उसके जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं देनी होंगी। इसके बाद सरकार कानून के अनुसार बच्चे को गोद लेना सुनिश्चित कर सकता है।

## कर्नाटक ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्योंकि जब से राज्य में सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी है, वह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के निर्णय एक के बाद एक पलट रही है, खासकर शिक्षा का भगवाकरण, फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही और साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश पर सख्त कदम उठाया जाना शामिल है।

कर्नाटक सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों में ''कर्नाटक मॉडल'' को प्रमुख रूप से चुनावी मुद्दे के रूप में पेश करना चाहती है।

## पुतिन ब्रिक्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है और अगर पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका में कदम रखा तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को उन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध के लिए वॉरंट जारी कर रखा है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के कुछ बच्चों को जबर्दस्ती रूस भेजने का निर्णय लिया था।

## 'बिहार कास्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्टे नहीं देगा, जब तक इसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई केस न बने।

सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केन्द्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को सात दिन में इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने की अनुमति दी। दरअसल, मेहता ने कहा था कि इस सर्वे के कुछ अवांछित परिणाम सामने आ सकते हैं। मेहता ने कहा था, ''हम इस या उस पक्ष के समर्थक नहीं है। लेकिन इस कवायद के कुछ (अवांछित) परिणाम हो सकते हैं, इसलिये हम अपना जवाब पेश करना चाहेंगे। लेकिन वे परिणामों के विस्तार में नहीं गये।

# इसरो की 2024 में मानवयुक्त स्पेस मिशन भेजने की योजना है

## इसरो इसके लिए स्टैप बाई स्टैप आगे बढ़ने का मिशन शुरु करने जा रहा है, पहला स्टैप-2023 के अंत में मानवरहित स्पेस मिशन, दूसरा स्टैप-2024 की शुरुआत में स्पेस में रोबॉट मिशन तथा तीसरा स्टैप-2024 के आखिरी महीनों में मानवयुक्त स्पेस मिशन

- **केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि, इसरो का अगला मिशन गगनयान है। इसके लिए इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में एक मानवरहित यान भेजा जाएगा। अगले वर्ष की शुरुआत में कृत्रिम मेधा युक्त रोबोट 'वायुमित्र' को भेजा जाएगा और इसकी सफलता एवं अध्ययन के बाद वर्ष 2024 के उत्तरार्द्ध में मानव मिशन भेजा जाएगा।**

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। सरकार चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर आत्मविश्वास से भरी है और उसका लक्ष्य अगले वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव मिशन भेजना है जिसके पहले एक कृत्रिम मेधा रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र पर लगे गोपनीयता के पर्दों को उतार कर इसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल दिया है जिससे इस क्षेत्र में नयी तकनीक और नयी प्रतिभाएं लाने का मार्ग खुल गया है।

डॉ. सिंह ने कहा कि इस समय तक 350 से अधिक स्टार्ट अप्स अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति करने के प्रस्ताव दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में बहुत तेजी आयी है और आज हम विश्व की महाशक्तियों के बराबरी के स्तर पर पहुंच गये हैं।

चंद्रयान-3 के मिशन के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रयान मिशन इस बार निश्चित रूप से कामयाब होगा और यह तय अवधि से अधिक काम करेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण की योजना में समय अवश्य लगा है लेकिन इससे खर्च कम हुआ और प्रतिरोध कम होने से मिशन सुरक्षित रहा है। 23 अगस्त को यह तय समय पर चांद की सतह पर उतरेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उतरने की सटीक जगह का निर्णय उसी समय किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसरो का अगला मिशन गगनयान है। इसके लिए इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में एक मानवरहित यान भेजा जाएगा। अगले वर्ष के पूर्वार्द्ध में कृत्रिम मेधा युक्त रोबोट 'वायुमित्र' को भेजा जाएगा और इसकी सफलता एवं अध्ययन के बाद वर्ष 2024 के उत्तरार्द्ध में मानव मिशन भेजा जाएगा।

डॉ. सिंह ने रूस के लूना-25 मिशन के क्रैश लैंडिंग और चंद्रयान मिशन को लेकर सावधानियों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत के चंद्रयान मिशन में कक्षीय आरोहण विधि से भेजा गया है। इसलिए इसमें प्रतिरोध कम होने के कारण ऊर्जा की खपत कम हो रही है और चंद्रमा के बहुत नजदीक आने के बाद ही वर्टिकल लैंडिंग करेगा और इस बार उसकी बॉडी में सुरक्षा के सभी उपाय किये गये हैं जिससे इस मिशन की विफलता की संभावना ना के बराबर है।

## अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंपने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सी.बी.आई. जांच का आदेश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि शिक्षक भर्ती घोटाले और नगर पालिका भर्ती घोटाले के बीच एक संबंध प्रतीत होता है। मामले की जांच सी.बी.आई. और ई.डी. कर रही है। जांच की जद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) सांसद अभिषेक बनर्जी भी आ गये हैं।

## गृह मंत्रालय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिकायतें मिली है। इनमें से 46,643 शिकायतें सिर्फ गृह मंत्रालय अफसरों के खिलाफ है।

देवेन्द्र यादव दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक है और वर्तमान में ए.आई.सी.सी. स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य है और उत्तराखंड के प्रभावी है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908